kilometres. We are doing our best to see that the fire is put off.

SHRI SANATAN BISI: Sir, my question is regarding safety measures. I am a Member of the Standing Committee on Labour Welfare. We visited Nagpur and found that there is no shelter facility for the mine workers. Moreover, the drinking water facility is also not there. Can the hon. Minister give an assurance that these facilities will be provided?

SHRI DILIP RAY: I will look into it.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, the coal sector mining is very obsolete in India basically because we do not use the modern technology. The coal mining rule stipulates whenever coal is mined, the empty pits are to be covered or to be filled up with send. The violation of that rule is the main reason why most of the labourers loss their lives.

Secondly, the Government does not explore the coal bed Methane trapped under the coal bed. That is the toxic gas which kills most of the labourers in the coal-fields. I would like to know whether the hon. Minister will make attempts to see that this coal bed methane is tapped with the help of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, because this is a very scarce resource in the country.

SHRI DILIP RAY: Sir, we are doing exactly the same thing. We are taking the help of the Ministry of Petroleum and Natural Gas in tapping this resource.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Sir, this is a question of accidents and safety. It is true that the Director of Mines Safety looks after the safety arrangements, but the Ministry of Coal is the nodal Ministry. I would like to know whether the Minister is aware that there was a Committee of Members of Parliament set up two years ago by the Consultative Committee attached to the Ministry of Labour. This Committee was set up in view of declining safety measures and failure on the part of the coal authorities to apprehend the officers or officials, who had been found to be responsible for the violation. If it is true, what has been the response of the Ministry to the long overdue recommendations made by that Committee. Mr. Chairman, Sir, I was the Chairman of that Committee?

SHRI DILIP RAY: Sir, I do not have the details now. I will look into it.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : What is this, Sir? This is a question of safety. Sir, my complaint is that nothing has been done.

SHRI T.N. CHATURVEDI : He has taken note of the Committee of which you were Chairman.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Sir, the hon. Member should not indulge in such a simple type of foolery.

MR. CHAIRMAN: Don't use the word foolery.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : Sir, thousands of people are involved. Why is the question of my name? It was a Parliamentary Committee and its recommendations were made available to the Ministry and the Ministry did not take any action.

SHRI T.N. CHATURVEDI : Sir, All I said was that probably the reply has taken note of the safety measures suggested by the Committee, of which he was the Chairman. I did not say... But, he should not use this word.

MR. CHAIRMAN: I have already said.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA : All right. I am sorry for that. I am only saying that the Government must be aware. The recommendation is pending with them. My complaint is that not a single recommendation of that Committee has been looked into till now by the Ministry.

SHRI DILIP RAY : I assure, I will look into it personally and come back.

मध्य प्रदेश और असम में ग्रामीण विकास योजनाएं

*304. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और असम में विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु कितना अंशदान किया जा रहा है तथा इन योजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इन योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन और मूल्यांकन में जन-प्रतिनिधियों की भागीदारी करने से वंचित रखा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOUDA PATIL): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The funds provided to Madhya Pradesh and Assam for implementation of various Rural Development Schemes in the last three years are indicated below:—

Year	Madhya Pradesh	Assam (Amount in Rs. Crores)
1996-97	698.57	220.96
1997-98	795.83	234.26
1998-99 (upto Feb. 1999)	780.74	290.63

The schemes are evaluated through Concurrent Evaluation and other specific studies sponsored by the Ministry. The Programme Evaluation Organisation of the Planning Commission also undertakes evaluation studies of the schemes.

(b) and (c) The programme guidelines provide for participation of the elected representatives like MPs and MLAs in planning, implementation and monitoring of the programmes. The MPs and MLAs are members of the Governing Bodies of the District Rural Development Agencies (DRDAs)/Zilla Prishad (ZPs) which approve the District Annual Action Plans.

The MPs and MLAs are also members of the Vigilance & Monitoring Committees at district and block levels. People's representatives are included in the State level Vigilance and Monitoring Committee also.

श्री गोविन्दराम मिरी: सभापति महोदय, पूरक प्रश्न पूछने से पहले मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने प्रश्न पूछा है कि विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए कितना अंशदान है केन्द्रीय सरकार का? एक तो योजनाओं का बाइफरकेशन नहीं किया गया है, टोटल दे दिया गया है। दूसरा, मैंने पूछा था कि योजनाओं की मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? इसके जवाब में उन्होंने कहा है कि योजना आयोग का कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन भी अध्ययन करता है। यह जवाब आया नहीं है। मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री सभापति: चलिए, जवाब दीजिए।

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, वह आया नहीं है। मैं पूरक प्रश्न अभी पूछ रहा हूं। मैं उनके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं यह बतला रहा हूं कि मेरा जो प्रश्न है उसका जवाब आया ही नहीं है।

सर, जो विभिन्न चार-पांच योजनाएं हैं जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है उसमें यह देखने में आया है, जैसे उदाहरण ले लीजिए—जवाहर रोजगार योजना जिसका नया नाम हो गया है—ग्रामीण समृद्धि योजना, सर, उसमें 1995-96 में कुल तीन हजार आठ सौ उन्नासी करोड़ रुपया आबंटित किया गया। उसके बाद वहां एक हजार सात सौ नब्बे करोड़ रुपया आबंटित हुआ। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लिए 1995-96 में जे॰आर॰वाई॰ में चार सौ आठ करोड़ रुपया आबंटित हुआ। उसके बाद 1996-97 में यह राशि घटाकर 176 करोड़ रुपया कर दी गई। यही प्रवृत्ति रोजगार आश्वासन योजना और आई॰आर॰डी॰पी॰ में है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, मेरा "क" भाग है—यह जो आबंटन राशि में लगातार घटोत्तरी हो रही है वह क्यों की गई है जबकि महंगाई बढ़ रही है? क्या इसकी वृद्धि करने जा रहे हैं? मेरा दूसरा "ख" भाग यह है—यह योजनाएं स्टेट गवर्नमैंट के हाथों में हैं और शिकायतें ऐसी मिलती है कि इस फंड का डॉयवर्सन होता है, दुरुपयोग होता है, भ्रष्टाचार होता है। तो क्या ऐसी शिकायतें उनको मिली हैं? अगर मिली हैं तो उनको दूर करने के क्या उपाय कर रहे हैं?

श्री सभापति: बस, हो गया। अब अगले में पूछिएगा।

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, the hon. Member has asked about the contributions being made by the Central Government towards the implementation of the various rural development programmes. We have given figures for 1996-97, 1997-98 and 1998-99. During 1996-97, in respect of Madhya Pradesh, we have released Rs. 690 crores. The State Government says the available money was Rs. 1182 crores and inflation was Rs. 770 crores. During 1996-97 Rs. 412 crores, which is a huge amount which remained unutilised. I am giving the figures about Madhya Pradesh only. During 1997-98, Rs. 795 crores was released by the Centre and the available money with the State was Rs. 1,382 crores. The unspent money is Rs. 257 crores. During 1998-99, the Central release was Rs. 290

crores. It is up to December. The money available during 1998-99 was Rs. 780 crores. The Central release and the money available was Rs. 1228 crores. The money spent was Rs. 710 crores. The money unspent was Rs. 517 crores.

श्री गोविन्दराम मिरी: मेरा जो प्रश्न था उसका जवाब अभी नहीं आया है। तभी मैं सप्लीमैंट्री पूछूंगा।

MR. CHAIRMAN: You put your second supplementary. Then, the Minister will reply.

श्री गोविन्दराम मिरी: सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि पैसे सैंट्रल गवर्नमैंट देती है, उसका उपयोग स्टेट गवर्नमैंट करती है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि पूरा पैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं। मैंने पूछा था कि इसमें सांसदों और विधायकों की क्या भूमिका है? जवाब में यह बताया गया है कि सांसदों और विधायकों को जिला ग्रामीण एजैंसीज और जिला परिषद में तथा जिला स्तर और ब्लाक स्तर पर समितियों में सदस्य बनाए जाते हैं। यह कागज में तो सही है लेकिन व्यवहारिक बात यह है कि हमारी जो परिस्थिति है सिर्फ we are there, but we have no role to play. और इतनी योजनाओं को कितना पैसा किस ज़िले में गया, उसका क्या उपयोग हुआ, उसका मॉनीटरिंग सिस्टम क्या है, किसी बात की जानकारी, मैं समझता हूं, मुझे तो जानकारी मेरे ज़िले में नहीं हो पाती। मैं नहीं जानता बाकी जगहों में क्या होगा? और सर, मध्य प्रदेश में डी॰आर॰डी॰ए॰ को एबॉलिश करके वहां पर ज़िला पंचायत बनाई गई है। ज़िला पंचायत के अध्यक्ष के नीचे हम लोग रहते हैं और क्या-क्या योजना बनाते हैं, क्या करते हैं, हम लोगों को न कभी कंसल्ट किया जाता है, न पूछा जाता है। ब्लॉक में जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, उसके नीचे हम लोगों को रहना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के जो पैसे हैं, जो योजनाएं हैं, जिन 5-6 योजनाओं को पैसा जाता है, क्या उसको मॉनीटर करने के लिए या जो ज़िला स्तर पर या ब्लॉक लेवल पर जो समिति बनी है, उसमें सांसदों को सभापति बनाने की कोई योजना है ताकि सांसदों को मालूम हो जाए कि इसका दुरुपयोग न हो?

दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पैसा योजना में सीधे पंचायतों को जाएगा? और यदि जाएगा तो क्या तरीका है कि पुन: डी॰आर॰डी॰ए॰ को जाएगा जिसमें दुरुपयोग होने की शिकायत मिली है, जिसमें पूरा पैसा उपयोग नहीं कर पाते हैं और उन राज्य सरकारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, two or three times, I wrote letters to all the Chief Ministers to involve the hon. M.Ps.in the planning and implementation of the programmes and also include the hon.Members in the Monitoring and Vigilance Committees. They have replied to them. In all the States, barring 40 districts, all the DRDAs have included the hon. Members in the Monitoring and Vigilance Committees. But I do not know whether the information has reached the Members or not. I will activate the Monitoring and Vigilance Committees and also see that information reaches hon. Members.

As regards the second question about distribution of money, we are not doing that. The state Governments, in accordance with the Finance Commission's recommendations, distribute the money. The criteria are approved by the State Governments only. We are not doing that. But, anyhow, I will consider the grievance of the hon. Members and I am going to articulate the role of hon. Members in the Monitoring and Vigilance Committees.

SHRI PARAG CHALIHA: Sir, for all the schemes like the Integrated Rural Development Programme and the Mahila Samridi Yojana, funds can be sent directly to the Gram Panchayats. Will the hon. Minister kindly consider and decide upon this?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, there are 2,27,000 Panchayats in our country. It is not possible to send funds directly from the Union Government to the Gram Panchayats. So, we are sending, releasing, funds at the District levels. From the Districts, the DRDA can release funds to the Gram Panchayats. That is the only possible thing.

MISS SAROJ KHHAPARDE: Sir, may I know from the hon Minister what the main schemes sponsored by the Central Government are for the development of rural areas in the States? And, what is the position in this regard in the State of Maharashtra?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, there are many schemes, the JRY, IAY, MWS, EAS, IRDP, DWACRA, TRYSEM, Improved Tool-Kit Programme, DPAP, DDP, ARWSP, NOPS, NFBS, NMBS, etc. As regards Maharashtra, Sir, I need a special notice.

MR. CHAIRMAN: Shri Arun Sarma. *(Interruption).*

कुमारी सरोज खापर्डे : सर, महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा।

श्री सभापति : उन्होंने कहा, मेरे पास इनफार्मेशन नहीं है, मैं बाद में दूंगा।

DR. ARUN KUMAR SARMA: Mr. Chairman, Sir, my question relates to the difficulties faced by the Government of Assam in the implementation of the IRDP programmes. Because of the difficult terrain, adequate branches of banks are not there. Also, the banks are reluctant to invest in Assam as well as in the other parts of the North-Eastern region. Under such circumstances, the benefits of the programmes have not gone to the rural population, the rural poor especially, for whom they are meant.

The Government of Assam has suggested that the IRDP Bank loan component should be delinked from the subsidy and the amount sould be substituted by the MPs and MLAs' Fund, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Boards, the Autonomous District Councils, NGOs and from other sources so that the beneficiaries could avail themselves of this opportunity. I want to know from the hon. Minister what action has been taken on the proposal of delinking the subsidy from the Bank loan component.

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, as regards the implementation of our programmes in Assam, I have received many complaints. I am going to hold an inquiry. Already, we have ordered an inquiry in Assam. As regards the subsidy, I do not know the banker's mind-set. They are a little bit reluctant. We held a meeting here, in Delhi, asking them to participate in our programmes, and we are pursuing the matter with the banks concerned. As regards the subsidy, we are going to restructure the programmes and we will see how best the subsidy can be effective.

DR. ARUN KUMAR SARMA: Will the subsidy be delinked from the bank loan component so that other agencies can help the beneficiaries who have otherwise to wait for years together to get loans from the bank?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, new programmes are on the anvil. We will consider the suggestion made by the hon. Member.

श्री राघवजी: सभापति जी, यह बड़े दुख और चिन्ता का विषय है कि मध्य प्रदेश में केन्द्र से 780 करोड़ रुपया वर्ष 1997-98 में रिलीज हुआ और उसमें से 517 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी की यह बात सही है कि उन्होंने पत्र लिखा हुआ है कि संसद सदस्यों को और विधायकों को कमेटी में शामिल किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं, मैं उस कमेटी में शामिल नहीं हूं, राज्य सभा के सदस्यों को कई स्थानों पर शामिल नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश में खासतौर से शामिल नहीं किया गया है और इसीलिए यह परिणाम निकल रहे हैं कि 517 करोड़ रुपया खर्च नहीं हो पा रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को जो योजनाएं भेजी हैं सुनिश्चित रोजगार योजना में शामिल करने के लिए और उस योजना में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में शिकायतें भेजी हैं, लेकिन एक भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या वह स्पष्ट निर्देश भेजेंगे कि राज्य सभा के सदस्यों को भी इन मानीटरिंग कमेटियों में और प्लानिंग कमेटी में शामिल किया जाए, जिला परिषद में शामिल किया जाए जिससे कि यह जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है, यह पैसा ठीक प्रकार से खर्च किया जा सके?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, already, they have formed 32 district-level Committees. They say they have included the hon. Members also in the Committees. Under the new programme, we are making some provision to consult the hon. Members in planning and implementation of the programmes.

Nuclear casualties

*305. PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA:†
SHRI RAGHAVJI:

Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news report which appeared in the Hindu of 30th December, 1998, under the capition, 'Army gearing up to face nuclear casualties';

(b) if so, whether AMC has devised a three-tier system of training for medical and para-medical personnel for tackling situation

† The question was actually asked on the floor of the House by Prof. Vijay Kumar Malhotra.